भारत को वैकल्पिक ऊर्जा चाहिये लेकिन वैं अलग राह अपनाने की जरूरत: अशीष कोठा

जो लोग मेगा ऊर्जा पार्क के लिए या खदान के विस्तार के लिए या बड़े विद्युत केंद्रों के लिए बलपूर्वक जमीनें लेने का विरोध क लेबल लगाया जा रहा है.

अशीष कोठारी 13 June, 2021 8:00 am IST

Advertisement

बिहार के धरनाइ गांव में सौर पैनल्स | प्रतीकात्मक तस्वीर | फोटो: आशीष कोठारी

जलवायु संकट पर पश्चिमी राष्ट्रों का दो-मुंहापन जगजाहिर है. उनके कई नेता इस पर चिंता जताते हैं और लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं है. जलवायु मुद्दे पर पाखंड का ताजा उदाहरण भारत-अमेरिकी जलवायु राष्ट्रपति जो बाइडन ने 22 अप्रैल को जलवायु पर शिखर सम्मेलन बुलाया था, उस दिन इसे अंतिम रूप दि

इस अवसर पर बयान में कहा गया है कि अमेरिका, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, अपने बड़े

जिससे वर्ष 2005 के 50-52 फीसदी के स्तर से 2030 तक इसे नीचे लाया जा सके.

Advertisement

भारत 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा की स्थापना कर, इस लक्ष्य को वर्ष 2030 तक हासिल करेगा. इस सा
गति को बढ़ाना है. स्वच्छ तकनीक आधारित नवाचार किए जाएं, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम किया जा स
इसका क्रियान्वयन हो. जलवायु बदलाव संबंधित जोखिम व प्रभाव को मापने, उसका प्रबंध करने के लिए

पर्यावरणविद इससे खुश हो सकते हैं कि तीन सबसे बड़े प्रदूषण उत्पन्न करने वाले देशों में से दो दुनिया क

कई विशेषज्ञों के मुताबिक बाइडन की घोषणा कुछ हद तक नाटकीय है. यहां निश्चित रूप से कुछ ताजी ह
जो जरूरत है उससे यह कदम बहुत कम है. ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक देशों को, जो हमें आपदा के क
इसकी अनदेखी करते हैं और हमें इस पर लगातार ध्यान दिलाना जरूरी है.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, व

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्व

अभी सब्सक्राइब करें

लेकिन मैं यहां भारत के इस समझौते में किये गये दावों का विश्लेषण करना चाहूंगा.

यह भी पढ़ें: एक नयी वैचारिक धुरी का निर्माण भारत की सबसे बड़ी चुनौती है: योगेंद्र याद

भारत के दावे और कुछ महत्वपूर्ण दोष

हाल के दिनों में भारत ने अपने आपको जलवायु जवाबदेही के मामले में वैश्विक नेता के रूप में पेश किया
आगे बढ़ा है. जैसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे काफी सराहना भी मिली है. पर इस पहल में **चार महत्**

अगर इनसे सरोकार रखें तो वास्तव में विश्व की जनसाधारण से सराहना मिलेगी, सिर्फ नेताओं से नहीं, जि

पहला: एक तरफ भारत में अक्षय ऊर्जा काफी बढ़ रही है लेकिन सरकार दूसरी तरफ जीवाश्म ईंधन में भ
कोयला खदानों की नीलामी की और इस दौरान नए तापीय ऊर्जा केंद्रों को शुरू करने की भी सोच जारी है
वाले क्षेत्रों में हैं, यही वे इलाके हैं जहां देश के सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से संवेदनशील आदिवासी रहते हैं

इससे जलवायु पर तिहरी मार पड़ेगी. कोयला के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, घने जंगलों के कटने
समुदायों का विस्थापन होगा और उन्हें औद्योगिक और शहरी रोजगारों के लिए धकेल दिया जाएगा, जहां
इस्तेमाल बढ़ेगा भी तो जलवायु परिवर्तन के लिये ये कोई मायने नहीं रखेगा, अगर जीवाश्म ईंधन का भी इ

यातायात इत्यादि क्षेत्र जो साझेदारी में शामिल किए गए हैं, उनमें कार्बन उत्सर्जन कम करने की बहुत क्षम
है, तथा इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अभी तक भारत में इस दिशा में कुछ बडे पैमाने पर ठोस काम

उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक यातायात में कुछ ध्यान पिछले कुछ वर्षों में दिया गया है लेकिन निजी क
यातायात में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. हालांकि कार्बन कम करने का वादा एक नेक इ
बनाए तो इससे लाभ संभव हैं.

दूसरा: भारत में अक्षय ऊर्जा की सरकारी परिभाषा में बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं. पिछले
सामाजिक रूप से यह हानिकारक और खतरनाक हैं. कई नई परियोजनाएं नाजुक हिमालय में प्रस्तावित हैं
उत्तराखंड की बाढ़ के बाद इन योजनाओं पर पुनर्विचार होगा या नहीं.

तीसरा: सरकार के रुख से लगता है कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर और पवन ज्यादातर मेगा पार्क के

वर्ष 2020 के उत्तरार्ध में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एक नोट में बताया है कि
किलोमीटर भूमि उपलब्ध है. इससे बेशकीमती चरागाह और पर्यावासों के नष्ट होने से गंभीर पारिस्थितिकी
आधारित संसाधन खत्म होंगे.

उदाहरण के लिए कर्नाटक के पावगढ़ सौर पार्क से कई कृषि व पशुपालक परिवार बेदखल हो गए और प
लगभग 60,000 हेक्टेयर जमीन ऊर्जा मेगा पार्क के लिए आवंटित की गई. इस साल जनवरी में मेरे एक
मालधारी समुदाय के लोगों ने इस बारे में मुझे बताया. उन्होंने कहा कि स्थानीय वन्य जीवों और यहां निवा
इस इलाके पर सदियों से निर्भर हैं.

इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन को पर्यावरण प्रभाव आंकलन व सरकारी स्वीकृति की भी जरूरत नहीं है क्यों
विकेंद्रीकरण की योजना भी है, जो स्वागत योग्य है, जैसे छत पर सौर पैनल की बड़ी संभावना है पर इसव
उत्पादन पर ज्यादा जोर है.

चौथा: सबसे महत्वपूर्ण, उपरोक्त सभी दोष इसलिए हैं क्योंकि ऊर्जा की बढ़ती मांग पर सरकार सवाल उ
मात्रा में ऊर्जा की मांग को बिना कुछ पूछे मानने को तैयार रही है और इसे पूरा करने के सभी संभव रास्ते

कोई भी ऊर्जा का स्रोत हो, अगर इसके इस्तेमाल को सीमित नहीं किया जाये, तो वो टिकाऊ नहीं है. जैसे लगता है लेकिन इसके लिए बिजली भी चाहिए और खनिज चाहिए, जो धरती से लगातार निचोड़े जा रहे हैं फिजूलखर्ची खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए. और बिजली का पुनर्वितरण करना चाहिए, जिनके पास पर कर रहे हैं, मुहैया कराना चाहिए.

ऊर्जा की अत्यधिक खपत वाले क्षेत्र जैसे शहरी निर्माण और निजी यातायात का विकल्प विकसित करना वह जलवायु का हो या जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य का- इससे समुदायों का विस्थापन और आजीविका का

यह भी पढ़ें: विपक्ष कमजोर हो गया, मोदी सरकार अब रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारियों की विश

लोकतंत्र को नज़रअंदाज करती ऊर्जा नीति

और अंत में, इस प्रकार की ऊर्जा नीति या समझौता लोकतंत्र को नज़रअंदाज करती है. जो लोग मेगा ऊर्ज केंद्रों के लिए बलपूर्वक जमीनें लेने का विरोध कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है. उन पर विकास 'देशद्रोही व राजद्रोही' कहा जा रहा है.

उत्तर के औद्योगिकीकरण और तथाकथित दक्षिण के विकास, जो असमानता व अन्याय के संबंध पर आध नागरिकों पर थोप रही है. उनकी जमीनें, पानी, जंगल बलपूर्वक छीन रहे हैं और इससे आत्मनिर्भर समुदाय जलवायु संकट को हल करने में कम ही मदद मिलती है. और इसकी पीठ पर बैठकर बड़े कार्पोरेट घराने जीवाश्म ईंधन या अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल से होने वाले पारिस्थितिकीय और सामाजिक प्रभाव से कोई ले

यह भी पढ़ें: कोरोना से आई तबाही के लिए क्या मोदी सरकार की स्वास्थ्य नीति जिम्मेदार है

अलग राह की जरूरत

उत्पादन के लिए उचित विकल्प हैं और विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा के भी कई विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें दुनिय 150 शासकीय स्कूलों की छत पर सौर ऊर्जा के लिए सहायता कर रही है. जिससे 8.8 करोड़ रुपए के बि बिजली विद्युत ग्रिड को वापस बेची जा सकेगी. इस प्रकार, एकीकृत माइक्रो ग्रिड (छोटे ग्रिड) से पूरे गांव प्रबंध भी हो सकेगा.

लेकिन इसमें भी वही बात दोहरानी होगी- सबसे महत्वपूर्ण है, मांग का नियंत्रण.

लद्दाख के सेक्मोल (SECMOL) और कच्छ की हुनरशाला जैसे समूहों ने यह दिखाया है कि किस तरह स आधुनिक तकनीक का मेल करती है, से वहां ऐसी इमारतें बनाईं गई हैं जिन्हें बहुत कम बिजली में गरम य में भी इसकी बहुत गुंजाइश है. ऐसे विकल्पों को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में शामिल किया जा सकता है, जिसक

हम सबको ऊर्जा की जरूरत तो है और हम इसके हकदार भी हैं. पर हम, खासकर हम में से अमीर, ज्यादा

इससे लगातार मुनाफा कमाने को बर्दाश्त किया जा सकता है और ना ही गैर टिकाऊ तरीके से इसके उत्

अगर हम इसमें विश्वास करते हैं कि प्रत्येक को बराबर बिजली मिलनी चाहिए, जो बुनियादी जरूरत के लि
रहे, तो हमें अपनी लगातार मांग पर नियंत्रण रखना होगा, साथ ही टिकाऊपन व समानता-न्याय की राह ३
राह पर चलकर वैश्विक अगुवाई करने की जरूरत है.

Advertisement

(अशीष कोठारी, कल्पवृक्ष व विकल्प संगम, पुणे से जुडे हैं, यह लेख बाबा मायाराम द्वारा ३

यह भी पढ़ें: 'नहीं, मैं एक पुरुष हूं'- गीत चतुर्वेदी के बहाने 'फैन कल्चर बनाम सरोकारी स

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

क्यों न्यूज़ मीडिया संकट में है और कैसे आप इसे संभाल सकते हैं

Advertisement

आप ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अच्छी, समझदार और निष्पक्ष पत्रकारिता की कद्र करते हैं. इस विश्वास